RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 261
दि. 22.01.2026, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूपी: पीठासीन सम्मेलन में बोले सीएम योगी- पीठ द्वारा विपक्ष को ज्यादा मौका देने पर नाराज नहीं होती सरकार

लखनऊ , (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा मंडप में बुधवार को तीन दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पीठ और सरकार की सोच प्रोएक्टिव (सक्रिय पहल की) होती है, रिएक्टिव (प्रतिक्रियावादी) नहीं होता। पीठ ने विपक्ष को अधिक मौका दे दिया तो सरकार रिएक्टिव नहीं होती।

योगी ने कहा कि पीठ पक्ष-विपक्ष में संतुलन बनाती है। सीएम ने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जहां भी ऐसे सम्मेलन होते हैं, दोनों लोग जाते हैं। वे केवल सदन की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहते। सीएम ने ऐसे सम्मेलनों को सीखो-सिखाओ का मंच बताया। योगी ने कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है।

न्याय, समता, बंधुता लोकतंत्र की आत्मा

उन्होंने कहा कि संविधान के तीन शब्द (न्याय, समता और बंधुता) भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसका कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है। समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं योगदान दे सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

जहां सहमति व असहमति के बीच भी संवाद के माध्यम से समन्वय होता है।

संसद हम सबके लिए प्रेरणा

पांच बार लोकसभा सदस्य रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में रहकर सीखा कि सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विधान सभा व विधान परिषद, संसद के नियमों-परिनियमों की जानकारी ले लें तो सदन संचालन में काफी आसानी होगी।

सीएम ने कहा, सतीश महाना ने 2022 में विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन सवा घंटे के प्रश्नकाल में केवल दो-तीन सदस्य ही बोल पाते हैं। क्या हम भी इसे संसद की तर्ज पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर उन्होंने तत्काल नियमावली में परिवर्तन किया। अब सवा घंटे में 20 तारांकित प्रश्न और हर प्रश्न के साथ दो-तीन अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले मंत्रीगण, दोनों पूरी तैयारी के साथ आते हैं। संसद हमारे लिए प्रेरणा बनी। संसद के प्रति श्रद्धा हर भारतवासी का दायित्व है। संसद को आदर्श के रूप में बढ़ाएंगे तो विधायिका और मजबूत-सशक्त होगी।

विधानमंडल की न्यूनतम 30 बैठकों के प्रस्ताव को बताया सराहनीय

सीएम ने कहा कि हम विजन 2047-विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। सीएम ने यूपी में सदन की कार्यवाही की प्रशंसा की। कहा, यहां कार्यवाही अत्यंत सुगमता से चलती है। सीएम ने वर्ष में कम से कम 30 बैठकों का प्रस्ताव पारित किए जाने को भी सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के लिए भी प्रेरणा है। जब सरकार के सामने यह बात आई कि ई-विधान होना है तो हमने कहा कि तत्काल इसे लागू कीजिए।

स्थाई विकास लक्ष्यों के लिए आए सुझावों को दे रहे आकार

सीएम ने कहा कि यूपी विधानसभा ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा-परिचर्चा चलाती है। स्थाई विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) पर भी यहां लगातार 37-38 घंटे चर्चा हुई। विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट में जनता से सुझाव लिए। पोर्टल पर 98 लाख लोगों के सुझाव आए। एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हम उसे फाइनल रूप दे रहे हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य विधानमंडलों में प्रति वर्ष कम से कम 30 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन जितना अधिक चलेगा, उतनी ही सार्थक चर्चा होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। नियोजित तरीके से सदन में बाधा डालना एक गलत परंपरा है, जिससे सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक का होता है, जिसकी समस्याओं पर चर्चा होनी होती है।

लोकसभा अध्यक्ष 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध का सबसे उचित मंच सदन है, जहां शब्दों और तर्कों के माध्यम से अपनी बात रखी जानी चाहिए। इससे जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास बना रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रयास होना चाहिए कि सदन एक घंटे के लिए भी बाधित न हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि हर क्षण जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

ओम बिरला ने जानकारी दी कि यह सम्मेलन छह महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि लोकसभा को इस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स से लैस किया जा रहा है और भविष्य में सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी विधानसभाओं को मानक तय करने होंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी राज्यों की विधानसभा की कार्यवाही एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि विधायिका को अधिक प्रभावी, जनोपयोगी और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से एक 'राष्ट्रीय विधायी सूचकांक' (नेशनल लेजिसलेटिव इंडेक्स) तैयार किया जाएगा। इससे विधानमंडलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संवाद की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक सम्पन्न

वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया एवं वन राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी बैठक में उपस्थित रहे

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जेसोर अभयारण्य को भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया

मुख्यमंत्री के संरक्षित वन क्षेत्रों में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर विजिटर्स पॉलिसी गाइडलाइंस बनाने के दिशानिर्देश

गांधीनगर, 21 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आयोजित स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक में जानकारी दी गई कि बनासकांठा के जेसोर भालू अभयारण्य

को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत विवरण में यह भी बताया गया कि रतनमहल अभयारण्य में बाघ की मौजूदगी देखी गई है और वहां उसके स्थायी रूप से बसने की पूरी संभावनाएं हैं।

इस संदर्भ में एनटीसीए की सहभागिता से इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण एवं देखभाल के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण स्थानीय लोगों को देने की योजना पर भी इस बैठक में सार्थक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वन विभाग को राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों/विजिटर्स की बढ़ती संख्या के कारण वन्यजीव जगत को किसी भी प्रकार का नुकसान या व्यवधान न हो, इसकी विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए।

एआई की ताकत मॉडल के आकार से नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र और उसके प्रभावी उपयोग से आती है: श्री वैष्णव

भारत एआई विकसित करने वाले अग्रणी देशों के समूह में शामिल, फोकस प्रसार और निवेश पर लाभ (आरओआई) पर केंद्रित: विश्व आर्थिक फोरम में श्री अश्विनी वैष्णव

सरकार 38,000 जीपीयू के माध्यम से किफायती एआई कंप्यूटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है: श्री अश्विनी वैष्णव

भारत ने एआई शासन के लिए तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण अपनाया, पूर्वाग्रह और डीपफेक का पता लगाना प्राथमिकता

अर्थव्यवस्था में एआई का प्रसार भारत की रणनीति का केंद्र

(जीएनएस)।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने

20 जनवरी 2026 को दावोस में विश्व आर्थिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में "एआई पावर प्ले, नो रेफरीज" शीर्षक वाली एक पैनल चर्चा के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अक) के प्रति भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें व्यापक स्तर पर एआई के प्रसार, आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी-कानूनी शासन पर जोर दिया गया।

श्री वैष्णव ने वैश्विक एआई गठबंधनों और भू-राजनीति से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत स्पष्ट रूप से एआई विकसित देशों के अग्रणी समूह में शामिल है। उन्होंने बताया कि एआई ढांचे में पांच स्तर होते हैं झ एप्लिकेशन, मॉडल, चिप, अवसंरचना और ऊर्जा; और भारत इन सभी पांचों क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, " एप्लिकेशन स्तर पर, भारत संभवतः विश्व को सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश होगा।"

केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह को 8.89 करोड़ रुपये का लाभांश सौंपा

वस्त्र मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8.89 करोड़ रुपये

का लाभांश चेक सौंपा । इस समारोह में वस्त्र सचिव श्रीमती नीलम शमी राव और संयुक्त सचिव श्रीमती पद्मिनी सिंगला भी उपस्थित थीं। सीसीआई के मुख्य प्रबंधक श्री ललित कुमार गुप्ता ने चेक सौंपा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने सीसीआई के निरंतर प्रयासों की सराहना की और भारत की कपास और वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में विकास, दक्षता, पारदर्शिता और नवाचार के महत्व पर जोर दिया।

उपराष्ट्रपति ने कहा – विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारत पर अपनी शर्तें न थोपे

उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु स्थित सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रजत जयंती समारोह में राष्ट्र निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया

उपराष्ट्रपति ने कहा – भारत प्रौद्योगिकी सृजनकर्ता के रूप में उभर रहा है

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु स्थित सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और संस्थान को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों की विशिष्ट सेवा पूरी करने पर बधाई दी।

उपराष्ट्रपति ने रजत जयंती समारोह को केवल समय के साथ संस्थान का बढना नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, दृढ़ता और उद्देश्य परक यात्रा बताया। उन्होंने सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के मूल मान्यता संबंधी

प्रतिबद्धता की सराहना की कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल कुशल पेशेवर ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक और नैतिकता पूर्ण प्रणेता भी तैयार करना है। उन्होंने संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद-एनएएसी द्वारा सर्वोच्च ए++ ग्रेड मान्यता दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने संस्थान के इनक्यूबेशन सेंटर और सभागार का भी उद्घाटन किया।

राज्यपाल पद के अपने कार्य अनुभव का स्मरण करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के श्रेणी निर्धारण और गुणवत्ता में सुधार पर लगातार जोर दिया था। उन्होंने कहा कि संस्थानों की खराब श्रेणी अक्सर शिक्षकों के रिक्त पदों की वजह से होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों की अच्छी संख्या शैक्षणिक मानक, विश्वसनीयता और जनविश्वास प्रत्यक्ष रूप से बढाती है।

श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सलाह दी कि वे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और दूसरों से अपनी तुलना किए बिना अपनी गति से लक्ष्य की ओर बढ़ें।

उन्होंने कहा कि भाग्य हर किसी का साथ नहीं देता, लेकिन कड़े परिश्रम और सत्यनिष्ठा से सफलता अवश्य मिलती है, भले ही यह तुरंत न मिले, लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ मिलती ही है।

भारत के नवाचार-संचालित विकास का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश अब केवल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी सृजनकर्ता के रूप में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने स्‍मरण कराया कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों से इससे निपटने के लिए औषधि विकसित करने का आह्वान किया था, तब देश ने चुनौती का सामना करते हुए सफलतापूर्वक स्वदेशी टीके विकसित किए, जो भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है।

'भारत के साथ बड़ा सौदा करेंगे...', ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा-फैंटास्टिक लीडर

(जीएनएस)।

विश्व आर्थिक मंच (World EcoQomic Forum) की बैठक के दौरान ऊ्‌ङ्ग२ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया. ट्रंप ने भारत के साथ मजबूत व्यापार समझौते को लेकर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें फैंटास्टिक लीडर बताया. भारतीय मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, विल हैव ए ग्रेट डील विध इण्डिया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर नई उम्मीद जगी है.

ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति गहरा सम्मान है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी वह कई मौकों पर पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा कर चुके हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं एक बार फिर तेज होने के संकेत दे रही हैं.

दोनों देशों के बीच तनाव भी देखने को मिले

हालांकि, बीते समय में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव भी देखने को मिला है. अगस्त में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया था, जो दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक थी. ये फैसला रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लिया गया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बातचीत रुक गई थी और कई मुद्दे अनसुलझे रह गए थे.

गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगा 'फेज्ड बैटल एरे'

भैरव लाइट कमांडो बटालियन का ऐतिहासिक डेब्यू

नई दिल्ली, (जीएनएस)। भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर एक नए अवतार में दिखाई देगा। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड न केवल 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद पहली बड़ी सैन्य प्रदर्शनी है, बल्कि यह भारतीय सेना की बदलती युद्ध रणनीति का गवाह भी बनेगी।

इस बार का मुख्य आकर्षण सेना का "फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन" होगा। इसके जरिए दुनिया पहली बार भारतीय सेना को युद्ध के वास्तविक अंदाज में मार्च करते देखेगी। इसके साथ ही, हाल ही में गठित 'भैरव लाइट कमांडो बटालियन' का डेब्यू और वंदे मातरम्‌ के 150 वर्षों का उत्सव इस समारोह को ऐतिहासिक बना देगा।

फीस्र४ु' ऊंट ढंश्ीं 2026

यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी और 'श्श्क्ढ' कल्चर के खात्मे जैसे बड़े बदलावों के साथ, यह परेड विकसित भारत की एक नई और सशक्त तस्वीर पेश करने के लिए तैयार है।

भारतीय सेना ने इस साल परेड की पारंपरिक शैली को बदलकर इसे पूरी तरह युद्ध जैसे क्रम में ढाल दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को यह दिखाना है कि वास्तविक युद्ध क्षेत्र में सेना किस तरह आगे बढ़ती है:

रणनीतिक क्रमः परेड में सबसे पहले दुश्मन की जानकारी जुटाने वाली टुकड़ियां चलेंगी।

हमलावर दस्ताः इसके पीछे भारी हथियारों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लैस मुख्य लड़ाकू यूनिट्स होंगी।

लॉजिस्टिक सपोर्टः अंत में सेना की रसद, संचार और चिकित्सा सहायता वाली सपोर्ट यूनिट्स दिखाई देंगी।

युद्ध गियरः सैनिक इस दौरान केवल औपचारिक वर्दी में नहीं, बल्कि अपने पूर्ण युद्ध उपकरणों और हथियारों के साथ नजर आएंगे।

भैरव लाइट कमांडो बटालियन का ऐतिहासिक डेब्यू

इस साल कर्तव्य पथ पर पहली बार 'भैरव लाइट कमांडो बटालियन' के जवान कदमताल करेंगे। इस विशेष यूनिट का गठन सामान्य पैदल सेना और हाई-प्रोफाइल स्पेशल फोर्सेज के बीच के अंतर को भरने के लिए किया गया है। यह बटालियन अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई और जटिल ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए तैयार की गई है।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दिखेगा संदेश

यह परेड पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के जवाब में की गई सीमा पार सटीक सैन्य कार्रवाई, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली राष्ट्रीय परेड है। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारतीय सेना के मनोबल और मारक क्षमता को एक नई पहचान दी है।

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में व्यापार की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र और ओडिशा के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में व्यापार की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

(जीएनएस)।

व्यापार और निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा (एनएलयूओ) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि केंद्र के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) चेयर्स कार्यक्रम के तत्वावधान में कटक स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा परिसर में "वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका" विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

इस सम्मेलन में ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिरजा प्रसन्ना

और प्रसन्ना सतपथी मुख्य अतिथि के रूप में तथा प्रोफेसर एन.एल. मित्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष राजदूत उजल सिंह भाटिया भी मौजूद थे।

सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय सचिवालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वर्नर ज्डौक; शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉ. कौशिक देब; व्यापार और निवेश कानून केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर जेम्स जे. नेदुमपारा; और अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास संस्थान में व्यापार और सतत विकास की निदेशक सुश्री एलिस टिपिंग ने विशेष संबोधन दिए।

सम्मेलन में हुई चचाओं का केंद्र बिंदु अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के संगम पर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की भूमिका थी। उच्च स्तरीय तकनीकी सत्रों में हरित औद्योगिक नीति, सतत व्यापार ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियां, नियामक प्रथाएं, कार्बन प्रशासन और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रत्येक पैनल चर्चा का समापन संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्रों के साथ हुआ, जिससे वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच सार्थक संवाद स्थापित हो सका। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षा जगत और नीति-निर्माण निकायों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने जलवायु और सतत विकास के उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को संरेखित करने पर अपने विचार साझा किए, जिससे नीतिगत संवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक रचनात्मक मंच के रूप में सम्मेलन की भूमिका रेखांकित हुई।

बिहार की विद्युत वितरण कंपनी देशभर में सर्वश्रेष्ठ,नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मिला स्वर्ण पुरस्कार

(जीएनएस)।

बिहार की बिजली वितरण कंपनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) ने देश भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन (एआईडीए) ने "डिजिटल पेमेंट में उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार" के लिए एनबीपीडीसीएल को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया है। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस (EDICON) 2026 के दौरान माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्रीमनोहर लाल ने ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकमनोज कुमार सिंह (भा.प्र.से) को पुरस्कार प्रदान किया।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री ने अळ&उ हानि में उल्लेखनीय कमी और वितरण कंपनियों की वित्तीय

स्थिति में सुधार के लिए बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण कंपनियां नागरिकों तक सेवा पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं, इसलिए उपभोक्ता संतुष्टि और डिजिटल सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कॉन्फ्रेंस के दौरान "स्मार्ट मीटर और डेटा विश्लेषण का प्रभावी उपयोग" सत्र को संबोधित करते हुए ऊर्जा सचिव ने कहा, "स्मार्ट मीटर का उपयोग न केवल राजस्व संग्रहण बल्कि उससे प्राप्त हो रहे डाटा के विश्लेषण के माध्यम से संचालन क्षमता को मजबूत करने एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।" राज्य में स्मार्ट मीटर के व्यापक अधिष्ठापन पर उन्होंने बताया, "वर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में बिहार में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2021 में राज्य की दोनों वितरण कंपनियां घाटे में थीं लेकिन विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन, डिजिटल पेमेंट में सुधार और बेहतर सेवा देने की प्रतिबद्धता के चलते दो साल के भीतर, वर्ष 2025 में, दोनों कंपनियों ने लाभ दर्ज किया।"

भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक नाय प्यी ताव में आयोजित

भारत-म्यांमार संयुक्त वार्ता ने कनेक्टिविटी, व्यापार सुविधा और एआईटीआईजीए कार्यान्वयन की समीक्षा की

भारत-म्यांमार व्यापार 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, 2030 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना दोनों पक्षों का लक्ष्य

(जीएनएस)।

भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की नौवीं बैठक आज म्यांमार के नाय प्यी ताव में आयोजित की गई। म्यांमार गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री यू मिन मिन और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में दोनों पक्षों के संबंधित हितधारक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक में कनेक्टिविटी में सुधार, बाजार पहुंच का विस्तार, वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाना, सीमा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन, सीमा व्यापार चौकियों को पुनः खोलना, रुपया-क्यात व्यापार निपटान प्रणाली को बढ़ावा देना और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के लाभों को अधिकतम करना सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। म्यांमार पक्ष ने भारत सरकार द्वारा म्यांमार के निर्यात, विशेष रूप से दालों और फलियों के क्षेत्र में, खुले और सहायक नीतिगत वातावरण बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त किया।

आपसी विकास को गति देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई, जिसमें वस्त्र, परिवहन और कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन, जहाजरानी, बिजली, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्वास्थ्य, औषधि और कृषि जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं और आपसी समर्थन एवं सहयोग के ढांचे को मजबूती मिल सकती है।

बैठक में सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए तामू-मोरेह और रही-जोखावथर सीमा व्यापार चौकियों के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की गई। भारतीय पक्ष ने इन स्थलीय सीमा चौकियों को शीघ्रता पूर्वक फिर से खोलने के अपने अनुरोध को दोहराया। दोनों पक्षों ने व्यापार दक्षता को और बढ़ाने के लिए तामू में एक एकीकृत चेक पोस्ट विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 के दौरान 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो एक मजबूत और सकारात्मक वृद्धि का संकेत है। आगे विस्तार की अपार संभावनाओं को देखते हुए, दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने आसियान-भारत व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, ताकि इसे सरल, संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और व्यापार को सुगम बनाने वाला बनाया जा सके।

इतने कम दाम पर मिलेगी बिजली, फडणवीस सरकार ने बनाई नई बिजली कंपनी

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्̄ य के किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने किसानों के लिए एक समर्पित बिजली कंपनी स्थापित की है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कंपनी का उद्देश्य किसानों को स्थायी और कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा दावेस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए दी। सीएम ने बताया कि किसानों को बिजली आपूर्ति करन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बिजली कंपनी बनाई है। इस बिजली वितरित प्रणाली के माध्यम से सौर ऊर्जा के माध्यम से लगभग 16 गीगावॉट बिजली उत्पन्न की जाएगी। उन्̄ होंने बताया इस साल के अंत तक ये प्रोजेक्̄ ट पूरा हो जाएगा।

महाराष्ट्र में किसानों को कितनी सस्ती मिलेगी बिजली?

कृषि में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग

को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के एक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीएम ने बताया कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के किसानों को अभी 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत आने वाले दिनों में राज्̄ य के किसानों को महज 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली का दाम देना पड़ेगा।

कब मिलेगी महाराष्ट्र के किसानों को सस्ती बिजली?

पूर्व के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (अक्कइ) के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। फडणवीस ने बताया कि राज्य ने दिसंबर 2026 तक विशेष रूप से कृषि उपभोक्ताओं के लिए 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह नई ऊर्जा कंपनी के जरिए वर्ष 2026 के अंत तक महाराष्ट्र के हर किसान तक सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करेगी।

फडणवीस ने कहा, "यह पहल किसानों को स्वच्छ ऊर्जा से अपने खेतों की सिंचाई करने में सक्षम बनाएगी। सौर पंप एक बड़ी वित्तीय राहत भी प्रदान करेंगे, क्योंकि किसानों को अगले 25 वर्षों तक इसके लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।"

आईआईसीडीईएम -2026 का संचालन शुरू हुआ

ईसीआई ने एक औपचारिक स्वागत समारोह में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों का स्वागत किया; इस कार्यक्रम में वृत्तचित्र श्रृंखला "इंडिया डिसाइड्स" की झलकियां भी दिखाई गईं

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का तीन दिवसीय सम्मेलन, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईआईसीडीईएम) 2026, आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ।

विशेष रूप से आयोजित एक स्वागत समारोह में, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों (ईसी) डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सम्मेलन का शुभारंभ एक भव्य उद्घाटन सत्र के साथ हुआ, जिसमें 42 चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के प्रतिनिधियों, 27 देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों, 70 से अधिक राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और देश भर के 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) सहित लगभग 1,000 लोगों ने भाग लिया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पिछले दशकों में निर्वाचन आयोगों के कार्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारत, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अभूतपूर्व पैमाने पर चुनाव कराता है, जिसकी जनसंख्या 1.5 अरब है।

निर्वाचन आयोग के डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने नागरिकों द्वारा ईएमबी में रखे गए विश्वास को अनमोल बताते हुए कहा कि हर चुनाव के केंद्र में एक नागरिक होता है, जिसे विश्वास होता है कि उसकी पसंद का सम्मान किया जाएगा और इसकी रक्षा करना ईएमबी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में, निर्वाचन आयोग के डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि आईआईसीडीईएम-2026 उन ईएमबी, शोधकताओं, छात्रों और पेशेवरों को एक साथ लाता है जो चुनावों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं और अपने-अपने संस्थानों में योगदान करते हैं।

आईआईसीडीईएम -2026 के विषय पर आईआईआईडीईएम के महानिदेशक श्री राकेश वर्मा ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का विषय, 'एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र', इस बात की व्यापक और बहुआयामी समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में लोकतंत्र को क्या प्रदान करना चाहिए।

प्रतिभागियों ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सहयोग से निर्मित आगामी वृत्तचित्र श्रृंखला "इंडिया डिसाइड्स" की झलकियां देखीं। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रबंध निदेशक श्री अर्जुन नोहवार ने अपने भाषण में कहा कि यह वृत्तचित्र श्रृंखला आकर्षक दृश्यों के माध्यम से एक ऐसी संस्था के कामकाज को दर्शाती है, जिसके पास दुनिया भर में सबसे जटिल दायित्वों में से एक है।

एसटीपीआई कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी में 'दूरसंचार में एआई' विषय पर इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्व-शिखर कार्यक्रम आयोजित

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के सहयोग से बुधवार आज नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर स्थित एसटीपीआई कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी में "दूरसंचार में एआई" विषय पर इंडिया झ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्व-शिखर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, ओईएम, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस बात पर विचार-विमर्श किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) किस प्रकार दूरसंचार नेटवर्क, सेवा वितरण और ग्राहक जुड़ाव के भविष्य को नया आकार दे रही है। यह कार्यक्रम भारत के एआई-संवर्धित डिजिटल अवसंरचना की ओर संक्रमण के दौरान वास्तविक उपयोग के मामलों, नीतिगत विचारों और कार्यान्वयन चुनौतियों को प्रदर्शित करने

के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

कार्यक्रम का शुभारंभ टीआरएआई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी, टीआरएआई के सदस्य श्री रितु रंजन मित्तर, टीआरएआई के सदस्य डॉ. एमपी तंगीराला, टीआरएआई के सचिव श्री अतुल कुमार चौधरी, एसटीपीआई के महानिदेशक श्री अरविंद कुमार और आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में एसटीपीआई के महानिदेशक श्री अरविंद कुमार ने स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उद्योग को जोड़ने वाले एआई-आधारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जिसे हम कभी एक साधारण पाइप कहते थे, वह अब एक बुद्धिमान पाइप में बदल गया है।" उन्होंने यह भी बताया कि आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिम्मेदार और प्रभावशाली एआई अपनाने के लिए एक समग्र और भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करेगा। इसके बाद टीआरएआई के सचिव श्री अतुल कुमार चौधरी ने सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में एआई के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और नैतिक सुरक्षा उपायों और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले नियामक ढांचों

संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा विकसित सम्पन्न पेंशन पोर्टल, उमंग पोर्टल के साथ एकीकृत हुआ

उमंग पर संपन्न के एकीकरण ने दूरसंचार विभाग के देश भर के लगभग 4 लाख पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ और जीवन प्रमाण पत्र की वैधता स्थिति की सुगम जांच को सक्षम बनाया

(जीएनएस)।

संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा विकसित सम्पन्न पेंशन प्रबंधन प्रणाली को उमंग (यूनिफायड मोबाइल एप्लिकेशन फॉरन्यू एज गवर्नेंस) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इस पहल से पेंशनभोगियों को उमंग वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर और जीवन प्रमाण पत्र (एलसी) की वैधता स्थिति प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हर समय उपलब्ध रहे।

दिल्ली के प्रधान संचार लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए) श्री आशीष जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि यह एकीकरण पेंशनभोगियों के लिए सुविधा बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन संबंधी जानकारी की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उमंग एप्लिकेशन के माध्यम से इन सेवाओं की उपलब्धता, हाल ही में किए गए डिजिलॉकर एकीकरण के साथ मिलकर, सभी पेंशनभोगियों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

उमंग एक एकल एकीकृत मंच है, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन और वेब

पोर्टल शामिल हैं, जिसके माध्यम से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सरकारी सेवाओं को कभी भी और कहीं भी एक्̄ सेस किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, यह एंड्रॉयड, आईओएस और वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे गूगल प्लेस्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से उमंग एप्लिकेशन का उपयोग करें और आधार कार्ड के माध्यम से प्रमाणीकरण करें।

संपन्न के बारे में: संपन्न (सिस्टम फॉर एकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन) विभाग का एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पेंशन प्रशासन और संबद्ध वित्तीय प्रबंधन कार्यों के लिए संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित, यह प्रणाली-केंद्रित प्रशासन से पेंशनभोगी-केंद्रित शासन की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवारों को अपने उचित लाभों का दावा करने के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

संपन्न ने पेंशन प्रक्रिया के संपूर्ण चक्र—मामलों की शुरूआत और प्रक्रिया से लेकर ई-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने, वितरण, लेखांकन, मिलान, वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा में सहायता और शिकायत निवारण तक- को डिजिटल कर दिया है। पेंशनभोगी अब सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करते हैं, जिससे बैंकों या सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है; वे भुगतान की स्थिति की जांच कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, ई-पीपीओ जनरेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या पते जैसे बदलावों का अनुरोध कर सकते हैं और घर बैठे शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। विभाग हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन भी संचालित करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न झ सम्पन्न सेवाओं को एक्सेस करने के लिए उमंग

1. उमंग क्या है?

उमंग एक एकल एकीकृत मंच (मोबाइल ऐप + वेब पोर्टल) है, जिसके माध्यम से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सरकारी सेवाओं का लाभ कभी भी, कहीं भी उठाया जा सकता है। यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और एंड्रॉयड, आईओएस और वेब पर उपलब्ध है।

2. उमंग को कैसे एक्̄ सेस करें?

ए. वेब पोर्टल के माध्यम से

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://web.umang.gov.in/

2. ऊपर दिए गए लॉगिन/रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

ु. मोबाइल ऐप के माध्यम से

1. गूगल प्लेस्टोर (एंड्रॉयड) या एप्पल स्टोर (आईओएस) से उमंग ऐप डाउनलोड करें।

सीटीआईएल और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने गांधीनगर में विधि एवं अर्थशास्त्र पर 9 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

सम्मेलन कानून, अर्थशास्त्र एवं व्यापार नीति पर विचार-विमर्श के लिए नीति निमार्ताओं, शिक्षाविदों व उद्योग जगत को एक साथ लाया

(जीएनएस)।

सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (सीटीआईएल) ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) के सहयोग से, जीएनएलयू के 'सेंटर फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स', 'सेंटर फॉर एम्पेरिकल एंड एप्लाइड रिसर्च इन लॉ एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज' और 'सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज' के माध्यम से, गांधीनगर में '9वें अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र सम्मेलन' (शासन और समावेशी सार्वजनिक नीति का अनुभवजन्य और अनुप्रयुक्त विधि और अर्थशास्त्र) का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

इस सम्मेलन में कानून और अर्थशास्त्र के इंटरफेस से जुड़े प्रमुख मुद्दों की जांच की गई, जिसमें नीति निमार्ताओं, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और उद्योग हितधारकों के दृष्टिकोण से व्यापार नीति की चुनौतियों को शामिल किया गया। इसमें पैनल चर्चा, तकनीकी सत्र और विशेषज्ञ पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। तीन दिनों के दौरान, इस सम्मेलन ने व्यापार नीति, शासन और समावेशी सार्वजनिक नीति को आकार देने वाले समकालीन कानूनी और आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए कानूनी शिक्षा जगत, न्यायपालिका, कानूनी अभ्यास, उद्योग और नीति निर्माण से जुड़ी प्रमुख हस्तियों को एक मंच पर लाया।

सीटीआईएल ने "बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) संधि (टीकेजीआर संधि) और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौता" तथा "स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापार के प्रति भारत का दृष्टिकोणः उभरती चुनौतियाँ और अंतराल" पर दो पैनल चचाओं का नेतृत्व किया।

उद्घाटन सत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और भारत के महान्यायवादी, श्री आर. वेंकटरमणी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने मुख्य भाषण में, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को न केवल कानून लागू करना चाहिए, बल्कि कानूनी व्याख्याओं के आर्थिक परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। भारत के महान्यायवादी, श्री आर. वेंकटरमणी ने नीति निमार्ताओं के सामने आने वाली उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं और अनुभवजन्य मॉडलों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस सम्मेलन में भारत भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कानून और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ-साथ जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया के म्योंगजी विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, जापान के तोम्योंगजी होकू विश्वविद्यालय और एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) सहित प्रमुख विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं ने भी विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ के हेड, प्रो. (डॉ.) जेम्स जे. नेडुम्परा ने "सेवा व्यापार और व्यावसायिक गतिशीलता" पर अपने विशेषज्ञ पूर्ण सत्र के भाषण में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते और भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा की, जिसमें प्राकृतिक व्यक्तियों की अस्थायी आवाजाही से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का विशेष संदर्भ दिया गया। उन्होंने सेवाओं की डिलीवरी के सीमा-पार तौर-तरीकों, वीजा संबंधी नियामक बाधाओं और पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए) की बढ़ती प्रासंगिकता पर भी विचार साझा किए।

सीटीआईएल द्वारा आयोजित एक पैनल ने डब्ल्यूआईपीओ टीकेजीआर संधि और डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स समझौते के बीच अंतसंबंधों की जांच की। सत्र के अध्यक्ष, प्रो. (डॉ.) उन्नत पंडित ने अपने विशेष संबोधन में भारत की पेटेंट प्रणाली की मजबूती और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ संरक्षित और एकीकृत करने में जैव विविधता विनियमन की सुगम भूमिका पर जोर दिया।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

झूठ, अफवाह और दुष्प्रचार का दुरुपयोग कर मादुरो भी हुए सत्ता से बाहर

रूस और चीन की मीडिया ने भी इसे ईंरान विरोधी प्रोपेगंडा व पश्चिमी दुष्प्रचार बताया। जबकि ठीक इसके विपरीत पूरे ईंरान में लाखों लोग वर्तमान ईंरानी सत्ता खासकर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के समर्थन में व अमेरिका-इजरायल के विरोध में सड़कों पर उतरे। कलयुग के ये सबल हथियार - झूठ, अफवाह और दुष्प्रचार वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी का राजधानी कोराकस से गत 3 जनवरी कोअपहरण कर ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा देने के नाम पर जिसतरह उन्हें न्यूयॉर्व ले जाया गया और उसके फ ौरन बाद जिस तरह ईंरान पर अमेरिकी हमले की भूमिका तैयार करने के लिये ईंरान में पिछले दिनों चले कथित सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को प्रचारित व प्रसारित किया गया इन घटनाओं इनसे जुड़ी ज़मीनी सच्चाईं ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या अब यह दुनिया पूरी तरह से झूठ,अफ वाह व दुष्प्रचार की गिरफ़्त में आ चुकी है? क्या आज की दुनिया में झूठ, दुष्प्रचार और अफ वाहें बहुत बड़ी ताक त बन चुकी हैं। इतनी बड़ी ताक त कि इनके बल पर कहीं चुनाव परिणाम भी उलट सकते हैं? अपने देश के विपक्ष या किसी देश की सत्ता को बदनाम किया जा सकता है? कहीं गृह युद्ध की आग भड़काईं जा सकती है? इसी के बल पर किसी देश को परमाणु हथियार रखने वाला तो किसी को केमिकल हथियार रखने वाला देश बताकर उस देश को ही तहसनहस किया जा सकता है? किसी स्वाभिमानी देश या शासक को नीचा दिखाने के लिये उसे तानाशाह या जनविरोधी वुछ भी बताकर वहां खूनी इबारत लिखी जा सकती है? निाति रूप से झूठ, अफ वाह और दुष्प्रचार सत्ता व राजनीति का हमेशा से ही प्रबल हथियार रहा है। खुद जर्मन तानाशाह हिटलर इसे एक प्रभावी हथियार मानता था। हिटलर का मानना था कि हमेशा एक ही बात को दोहराओ, चाहे वो कितनी भी सरल क्यों न हो। वह कहता था कि प्रोपेगैंडा में सच्चाईं को थोड़ा-सा मिलाकर झूठ को और प्रभावी बनाया जा सकता है। और उसी का मत यह भी था कि झूठ इतना बड़ा होना चाहिए कि कोईं सोचे भी नहीं कि कोईं इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। खुद हिटलर ने इसी नीति का इस्तेमाल यहूदियों के विरुद्ध कर दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार अंजाम दे डाला। इसी तरह 2002-2003 का वह दौर याद कीजिये जब अमेरिका ने तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर रासायनिक हथियार और अन्य सामूहिक विनाश के हथियार रखने का गंभीर आरोप लगाया था। इस आरोप को अमेरिका ने इतना प्रचारित किया था कि इसी आधार पर मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला तक कर दिया। सद्दाम को अपदस्थ कर उसे सामूहिक हत्या के दूसरे मामले में फांसी के पंदे पर चढ़ा दिया। बाद में रिपोर्ट आईं कि इराक के पास कोईं सव्रिय या बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों का भंडार नहीं मिला। कोईं रासायनिक हथियार उत्पादन, कोईं र्द्में गैस का बड़ा भंडार, कोईं मोबाइल बायोलॉजिकल लैब आदि वुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि अमेरिका ने बाद में खुद यह स्वीकार भी किया कि उसकी खुफि या जानकारी गलत थी। इराक पर हमले का आदेश देने वाले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी उस समय यही कहा था कि 'वे भी निराश हैं'। कईं अमेरिकी अधिकारी और पूर्व खुफि या प्रमुखों ने इसे खुफि या विफलता यानी ग्हाूत्त्गुाहम ग्त्ल भी कहा। परन्तु तब तक तो झूठ अफ वाह और दुष्प्रचार का निशाना सद्दाम हुसैन बन चुके थे। उसके बाद इसी बहाने इराक से तेल दोहन से लेकर इराक को अस्थिर व तबाह करने तथा वहां अमेरिकी सैन्य बेस बनाने तक के कईं खेल खेले गए। अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो पर भी मुख्य रूप सेनारको-टेररिज़्म, कोकीन आयात की साज़िश , मशीन गन और विनाशकारी उपकरणों का क ब्ज़ा और उपयोग तथा मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की साज़िश जैसे आरोप लगाए हैं। परन्तु उन्होंने मादुरो की गिरफ़्तारी के फ ौरन बाद ट्रंप ने कहा - कि अमेरिका वेनेज़ुएला को संचालित करेगा, खासकर इसके तेल भंडार और तेल उद्योग को।

टैरिफ से धमकाने वाले ट्रंप को झटका, 27 देशों ने किया बड़ा फैसला, भारत को क्या होगा फायदा?

भारत समेत अन्य देशों को ट्रेड टैरिफ लगाकर धमकाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोहरा झटका लगने वाला है। क्योंकि यूरोपीय संघ (EU) 27 जनवरी को भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा करेगा। इस डील से भारतीय उत्पादों को EU बाजारों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंच मिलेगी। ट्रंप के लिए 'दोहरे झटके' इसलिए है क् योंकि एक ओर एव भारत से निकटता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ उसके व्यापार समझौते पर तलवार लटक रही है।

EU अमेरिका के साथ व्यापार समझौता निलंबित कर सकता है

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति से जुड़े बीबीसी सूत्रों के मुताबिक, फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट बुधवार, 21 जनवरी, 2026 को अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते को निलंबित करने का ऐलान कर सकती है।

EU में हैं 27 देश

याद रहे यूरोपीय संघ (EU) यूरोप के 27 देशों का एक साझा मंच है, जो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। यह संगठन अपने सदस्य देशों के बीच शांति बनाए रखने, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम करता है, ताकि पूरे यूरोप में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

अमेरिका-EU के बीच पिछला व्यापार समझौता क्या था?

पिछले साल जुलाई में स्कॉटलैंड में हुए इस समझौते में अमेरिका ने यूरोपीय सामानों पर टैरिफ 30% से घटाकर 15% कर दिया था, बदले में यूरोपीय देशों ने अमेरिका में निवेश और निर्यात बढ़ाने पर सहमति दी। हालांकि, अब ट्रंप ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोप पर दबाव बनाने के लिए अगले महीने से 10% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं।

ट्रंप अब EU पर नए टैरिफ क्यों लगाने की धमकी दे रहे हैं?

ट्रंप की टैरिफ धमकियों से यूरोपीय देश नाराज हैं। उन्होंने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये वही देश हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के ट्रंप के फैसले का खुलकर विरोध किया था।

किन यूरोपीय देशों पर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगाया है?

18 जनवरी को ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट में लिखा, जिसमेंफरवरी से आठ देशों पर टैरिफ लगाया गया है, इनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड के सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा और यह बढ़ भी सकता है।" ये सभी देश ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के साथ हैं और ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध किया था।

ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियां अमेरिका के लिए खतरा हैं, इसलिए वह इस पर तत्काल अमेरिकी नियंत्रण चाहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है और लगभग 300 सालों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है।

ग्रीनलैंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है?

ग्रीनलैंड लगभग 300 वर्षों से डेनमार्क का हिस्सा है

1979 से इसे स्वायत्तता प्राप्त है

विदेश और रक्षा मामलों में डेनमार्क निर्णय लेता है

डेनमार्क नाटो का सदस्य है, इसलिए ग्रीनलैंड को NATO सुरक्षा प्राप्त है

नमार्क नाटो (NATO) का सदस्य होने के कारण ग्रीनलैंड को इस संधि के तहत सुरक्षा प्राप्त है।

यूरोपीय देशों की ट्रंप की टैरिफ नीति पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के फैसले का ब्रिटेन और फ्रांस ने विरोध किया, फ्रेंच विदेश मंत्री ने टैरिफ को 'ब्लैकमेलिंग' करार दिया। इस बीच, 27 जनवरी को होने वाले भारत-एव FTA से दोनों देशों को बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय व यूरोपीय उत्पादों को कम या शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा।

भारत-एव FTA से दोनों पक्षों को क्या फायदा होगा?

इसके साथ ही, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया है, जो वैश्विक व्यापार में जटिलताओं को बढ़ाता है।

डराता रहा पानी-सरिया-अंधेरा...कुहासे में डूबा सिस्टम और गड्ढे में समा गया युवराज

(जीएनएस)।

नोएडा सेक्टर 150 की उस रात को लोग कुहासे की रात कह रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उस रात धुंध सड़कों पर नहीं, पूरे सिस्टम की आंखों पर छाई हुई थी। 27 साल का युवराज मेहता, जो दिनभर कोड लिखकर अपने भविष्य के सपने बुनता था, उसी सिस्टम के गड्ढे में समा गया जिसे हम विकास कहते नहीं थकते। गुरुग्राम से लौटते वक्त उसकी कार एक ऐसे पानी भरे गड्ढे में गिरी, जिसे किसी ने गड्ढा मानने की जरूरत ही नहीं समझी थी।

बरसात का पानी, खुले लोहे के सरिए, टूटी दीवार और लापरवाही से छोड़ी गई एक कंस्ट्रक्शन साइट। यह सब किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के सबसे मॉडर्न कहे जाने वाले इलाके की हकीकत थी। युवराज कार की छत पर चढ़ा रहा, सांसें गिनता रहा और पिता को फोन कर आखिरी उम्मीद के साथ चिल्लाता रहा। सिस्टम ने मानों कान-आंख ही बंद कर लिए हों। सुबह जब जवाब आया, तब सिर्फ एक लाश बची थी।

इसे हादसा कहना भी अब एक तरह का मजाक लगता है। पुलिस आई, अग्निशमन दल आया, एसडीआरएफ भी आई, लेकिन सबके पास एक न एक बहाना था। पानी ठंडा है, नीचे सरिया है, अंधेरा है, रिस्क है। आपदा राहत के नाम पर करोड़ों के बजट वाले विभाग के पास एक लंबी रस्सी तक नहीं थी। उस रात सबसे बहादुर कोई अफसर नहीं, बल्कि एक डिलिवरी बॉय मोरिंदर निकला, जिसने जान जोखिम में डालकर पानी में छलांग लगा दी। युवराज बच नहीं सका, लेकिन इतिहास अगर ईमानदार हुआ तो उस डिलिवरी बॉय को बहादुर और सिस्टम को कायर जरूर लिखेगा।

युवराज की लाश तो निकाल ली गई, लेकिन सवाल जिंदा रह गए। थोड़ी सी मुस्तैदी होती, थोड़ी सी इंसानियत होती, तो शायद एक पिता का बेटा आज जिंदा होता। मौत के बाद बिल्डर गिरफ्तार हुआ, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पद से हटाए गए और अब शायद जांच, इंक्वायरी और फाइलें चलेंगी। मगर जिनके अधीन पूरा प्रशासन, एसडीआरएफ और

व्यवस्था आती है, उन पर सवाल उठाना अब भी असुविधाजनक माना जा रहा है।

सेक्टर 150 को कभी रस्ह१३२ ड्३८ बनाने का सपना दिखाया गया था। आज वहां अपार्टमेंट कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। आधे से ज्यादा मकान बिना रजिस्ट्रेशन बिक रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। सवाल सिर्फ उस बिल्डर का नहीं जिसने पानी भरा बेसमेंट खुला छोड़ा, सवाल उस अथॉरिटी का भी है, जिसने उसे इजाजत दी। सवाल उस दीवार का भी है, जो टूटी और फिर कभी बनाई नहीं गई? सवाल उस फ्ळड का भी है, जिसने ट्रक और ड्राइवर को लाइसेंस दिया? सवाल उस रउभ्ऋका भी है जिसे तैरना नहीं आता और उस फायर ब्रिगेड का भी, जिसके पास रस्सी नहीं?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युवराज की जगह अगर कोई बड़ा नेता, अफसर या वीआईपी होता तो भी यही तमाशा होता? क्या तब भी पानी ठंडा लगता, सरिए डराते और अंधेरा आड़े आता? युवराज कोई खास आदमी नहीं था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।

युवराज एक नाम नहीं, एक आम आदमी है। वही आम आदमी जो नमक से लेकर सैलरी तक हर चीज पर टैक्स देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जिसकी जान की कीमत शून्य हो जाती है। उस रात कुहासा सिर्फ मौसम का नहीं था, वह हमारी व्यवस्था की सोच का था।

भारतीय टी20 टीम ने नए साल के पहले टी-20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रनों से करारी शिकस्त दी

भारतीय टी20 टीम ने नए साल के पहले टी-20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रनों से करारी शिकस्त दी है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया और फिर कसी हुई गेंदबाजी के दम पर कीवी टीम को लक्ष्य से काफी दूर रोक दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत ने बनाए 238 रन

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले भारत ने साल 2023 में कीवियों के खिलाफ 234 रनों का स्कोर बनाया था, जिसे आज अभिषेक शर्मा (84)

और रिंकू सिंह (44*) की तूफानी पारियों के दम पर पीछे छोड़ दिया गया।

190 रन ही बना सकी न्यूजीलैंड

लक्ष्य के दबाव में बिखरी टीम 239 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरूआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने पावरप्ले से ही दबाव बनाए रखा। हालांकि, मध्यक्रम में कीवी बल्लेबाजों ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन रन-रेट का बढ़ता दबाव उनके विकेट गिरने का मुख्य कारण बना। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी।

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने किया। गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड को कभी भी मैच में हावी होने का मौका नहीं दिया। विशेषकर डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का बेहतरीन मिश्रण किया। अगले मुकाबले की तैयारी इस बड़ी जीत ने न केवल भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों को भी पुख्ता किया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी टीम के इस संतुलित प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आए।

अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी (शुक्रवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम जहाँ वापसी की कोशिश करेगी, वहीं भारत की नजरें अपनी बढ़त को दोगुना करने पर टिकी होंगी।

अमेजन ने भारत में ऑल-न्यू इको शो 11 और फोर्थ-जनरेशन इको शो 8 का लॉन्च किया

लखनऊ, 21 जनवरी 2026: आज अमेजन ने भारत में एलेक्सा के साथ अपने ऑल-न्यू इको शो 11 और फोर्थ जनरेशन इको शो 8 स्मार्ट डिस्प्ले पेश किए। इन डिवाईसेज में ऑल-न्यू ऑडियो आर्किटेक्चर और डेल्ल्रशील्लरी कस्टम सेंसर प्लेटफॉर्म है। साथ ही एज-टू-एज डिस्प्ले और थिन बेजेल के साथ इन्हें बिल्कुल नया डिजाईन दिया गया है। ये डिवाईस डीप बेस और स्पष्ट आवाज के साथ स्मार्ट होम रूटीन को आसान बना देती हैं। इनमें मोशन, प्रेजेंस और तापमान सेंसर दिए गए हैं। इको शो 11 और इको शो 8 क्रमशः 11 इंच और 8.7 इंच का व्यूईंग एरिया प्रदान करते हैं।

इको शो 11 और इको शो 8 में ऑन-स्क्रीन टच कंट्रोल या एलेक्सा को हैंड्स-फ्री वॉईस कमांड देकर स्मार्ट होम रूटीन संचालित किए जा सकते हैं। कंपैटिबल ऐप्स से ऑडियो-विज्युअल कंटेंट का आनंद लिया जा सकता है। कैलेंडर तथा शॉपिंग लिस्ट संभालने तथा रेसिपी आदि देखने जैसे दैनिक काम आसानी से किए जा सकते हैं।

दिलीप आर.एस., डायरेक्टर और कंट्री मैनेजर, अमेजनडॉटइन डिवाइसेस इंडिया ने कहा, ह्लइको शो 11 और इको शो 8 फैमिली शेड्यूल में तालमेल बनाने, स्मार्ट होम मैनेज करने, और व्यस्त दिनचर्या का प्रबंधन करने जैसे सभी काम संभाल सकते हैं। ये डिवाइस होम असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं। ग्राहकों को ऑर्गनाइज्ड और कनेक्टेड रखती हैं, तथा उनके अनुरूप खुद को ढाल लेती हैं। ये सभी रूटीन काम संभाल लेती हैं ताकि ग्राहक ज्यादा जरूरी कामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। मैं डेल्ल्रशील्लरी टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड ऑटोमेशन, नई ऑडियो अनुभव और एलेक्सा के साथ सुगम हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल के साथ इन डिवाइसेज को ग्राहकों के जीवन का हिस्सा बनते देखने के लिए उत्साहित

हूँ.ह्व

एडवांस्ड होम ऑटोमेशन बढ़ाता है सुविधा और आराम

इको शो 11 और इको शो 8 में कस्टम डिजाईन की अे3 ढ१ङ्क सिलिकॉन चिप दी गई है, तो बहुत तेज परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। इस सिलिकॉन चिप के साथ कस्टम सेंसर प्लेटफॉर्म, डेल्ल्रशील्लरी है, जो एंबियंट अक के लिए बनाया गया है। यह कई सेंसर और सिग्नल्स का उपयोग करता है, जिनमें 13 मेगापिक्सल (एम.पी) का कैमरा, ऑडियो, अल्ट्रासाउंड वाई-फाई राडार, एक्सेलेरोमीटर और वाई-फाई सीएसआई शामिल हैं, जो व्यक्तिगत, प्रोएक्टिव और मददगार एलेक्सा अनुभव संभव बनाते हैं।

इससे ऑटोमेटेड प्रतिक्रियाएं संभव होती हैं, जैसे जब कोई कमरे में प्रवेश करता है, तो ऑटोमेटेड लाईट अपने आप जल जाती हैं, या जब तापमान एक निश्चित स्तर पर पहुँच जाता है, तब तापमान पर आधारित दिनचर्याएँ अपने आप शुरू हो जाती हैं। ग्राहक एलेक्सा ऐप की मदद से स्मार्ट होम रूटीन स्थापित कर सकते हैं।

अधिकतम व्यूईंग एरिया और एंबियंट विज्युअल्स का आनंद लें

इको शो 11 और इको शो 8 में क्रमशः 11 ईंच फुल ल्ऊ और 8.7 ईंच ल्ऊ एज-टू-एज ग्लास डिस्प्ले दिए गए हैं। ये विस्तृत कलर्स के साथ शार्प पिक्चर प्रदान करते हैं। नए डिजाईन को ज्यादा स्लीक बनाया गया है। इसमें 3ऊ-निट फैब्रिक के साथ थिन बेजेल्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ा व्यूईंग एरिया मिल सके। साथ ही, एंबियंट विज्युअल वातावरण के अनुरूप अनुकूलित होकर आरामदायक व्यूईंग प्रदान करता है। इसके हाई डेफिनिशन डिस्प्ले के साथ 13 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं, जो सेंटर्ड ऑटो-फ्रेमिंग और नॉईज रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों और परिवार से स्पष्ट वीडियो कॉल और बातचीत संभव बनाते हैं, जो एलेक्सा ऐप या इको स्मार्ट डिस्प्ले के माध्यम से संभव होती है।

जितेंद्र सिंह मीडिया राउंड टेबल पर पत्रकारों से रूबरू हुए-कहा उन्होंने स्पष्ट किया कि पारित परमाणु विधान पर 'कड़े समय सीमाओं' के बिना, उचित जांच के बाद नियम अधिसूचित किए जाएंगे

परमाणु ऊर्जा सुधारों में निर्णायक मोड़ पर भारत, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का लक्ष्य: डॉ. जितेंद्र सिंह

सरकार सावधानीपूर्वक परमाणु नियम बनाएगी; सुरक्षा और संरक्षण अटल: डॉ. जितेंद्र सिंह

गगनयान मानवरहित मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले, 2026 की दूसरी छमाही में संभावित: डॉ. जितेंद्र सिंह

₹1 लाख करोड़ आरडीआई कोष प्रयोगशाला से बाजार तक संक्रमण को तेज करेगा; पहली किश्त शीघ्र अपेक्षित, डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तथा पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायतें, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम निर्णायक मोड़ पर है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सुधार किए जा रहे हैं, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को कायम रखा जा रहा है।

मीडिया राउंड टेबल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति से जुड़े व्यापक मुद्दों पर, मंत्री ने कहा कि सरकार हाल ही में पारित परमाणु विधान के तहत विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि "कड़े समय सीमाओं" के बिना, उचित जांच के बाद नियम अधिसूचित किए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा संरक्षण, हितधारकों की चिंताओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया ढांचा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल देगा। "हम गैर-सरकारी भागीदारी को खोल रहे हैं, जिसमें निजी खिलाड़ी भी शामिल हैं, बिना आवश्यक संरक्षणों पर समझौता किए," उन्होंने कहा। मंत्री ने कहा कि एक बार नियम लागू होने पर, अधिनियम के तहत कल्पित वैधानिक निकाय, जैसे सशक्त परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक इकाई के रूप में और परमाणु ऊर्जा निवारण आयोग, को कानून में पहले से निर्धारित संरचना और जनादेश के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

लागत संबंधी चिंताओं पर, मंत्री ने स्पष्ट किया कि जबकि हल्के जल रिएक्टर वर्तमान में स्वदेशी दाबित

भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की तुलना में अधिक महंगे हैं, लेकिन पैमाने, विनिर्माण के स्थानीयकरण और घरेलू भागीदारी में वृद्धि के साथ लागत कम होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को खोलना बड़े निवेश आकर्षित करने और दक्षता लाने का भी उद्देश्य है।

दायित्व संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि संचालक-आपूर्तिकर्ता दायित्व ढांचा यथावत है। संचालकों और आपूर्तिकताओं के बीच कोई भी संविदात्मक व्यवस्था अनुमत है, लेकिन सरकार ऐसी समझौतों का पक्षकार नहीं होगी।मंत्री ने विधान पारित होने के बाद घरेलू निजी खिलाड़ियों और विदेशी सहयोगियों दोनों से प्रोत्साहनजनक रुचि पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया भारत के परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र और दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा रणनीति में वैश्विक विश्वास को दशार्ती है।

अंतरिक्ष क्षेत्र पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल के प्रक्षेपण असफलताओं से भारत की विश्वसनीयता प्रभावित होने के सुझावों को खारिज कर दिया। "हर अंतरिक्ष मिशन की कठोर समीक्षा की जाती है। हम इसे विश्वसनीयता की हानि के रूप में नहीं देखते, विदेशी उपग्रह भारतीय प्रक्षेपण सेवाओं के लिए कतार में लगे रहते हैं," उन्होंने कहा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि पिछले एक दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सरकारी समर्थन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, प्रमुख विभागों के बजट दोगुने से अधिक हो गए हैं। इसी समय, अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर-सरकारी इकाइयों के लिए खोलने से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था दृश्यमान और जीवंत बनी है, जो लगभग 8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और आने वाले वर्षों में 20-25 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

गगनयान कार्यक्रम पर अपडेट देते हुए, मंत्री ने कहा कि मानवरहित जी1 मिशन 2027 में प्रस्तावित मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले होगा, हालांकि यह 2026 की दूसरी छमाही में हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान अत्यधिक सावधानी और नौसेना सहित बहु-एजेंसी समन्वय की मांग करती है, ताकि सुरक्षित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर दिया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का शासन और जनकल्याण के लिए उपयोग है, जो गति शक्ति के तहत अवसंरचना निगरानी, दूर चिकित्सा और कृषि से लेकर स्वामित्व कार्यक्रम के तहत ड्रोन-आधारित भूमि मानचित्रण तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि इन अनुप्रयोगों का व्यापक सामाजिक प्रभाव होने के बावजूद अक्सर इनकी रिपोर्टिंग कम होती है।

₹1 लाख करोड़ के कोष वाले अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष पर, मंत्री ने कहा कि महीने के अंत तक लगभग ₹4,000-5,000 करोड़ की पहली किश्त जारी होने की उम्मीद है। उन्होंने सूचित किया कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बायरैक) को द्वितीय स्तर के कोष प्रबंधकों के रूप में चिह्नित किया गया है ताकि पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि आरडीआई कोष प्रयोगशाला अनुसंधान और बाजार-तैयार प्रौद्योगिकियों के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं, जहां भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ कुछ चुनिंदा देशों में से एक है।

सीआरपीएफ के जांबाजों के बच्चों ने मैदान पर गाड़ा झंडा

वारियर्स ने जीता चंद्रावल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब,

लखनऊ। चंद्रावल ग्रामसभा के भोनेवाल क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में वारियर्स क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। CRPF कार्मिकों के बच्चों से सजी इस टीम ने अपने अनुशासन और बेमिसाल खेल कौशल से 32 टीमों को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

फाइनल मुकाबला वारियर्स टीम और कैथी लखनऊ के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वारियर्स टीम ने निर्धारित 15 ओवरों में 156 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से सोनू ने मैदान के चारों तरफ शॉट खेलते हुए महज 28 गेंदों में 12 छक्कों की मदद से 92 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके इस प्रदर्शन ने विपक्षी टीम के हौसले पस्त कर दिए।

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैथी की टीम वारियर्स की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम महज 70 रनों पर सिमट गई।

रविश विक्रम सिंह ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में मात्र 4 रन देकर विपक्षी टीम के 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। पूरे टूर्नामेंट में बाएं हाथ के गेंदबाज इंद्रजीत का जादू सिर चढ़कर बोला, उन्होंने कुल 7 विकेट लेकर टीम को फाइनल तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

टूर्नामेंट के समापन पर शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, बेस्ट बल्लेबाज, विकास बाजीगर बेस्ट बॉलर, पियूष,

वारियर्स टीम की विशेषता यह है कि इसके सभी सदस्य लखनऊ में रह रहे उपद्धऋ कार्मिकों के बच्चे हैं। टीम की इस उपलब्धि ने युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग और गलत गतिविधियों से दूर रहकर खेलों के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, स्वास्थ्य और अनुशासन से जुड़ने का सकारात्मक संदेश दिया है। यह जीत खेलो इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी प्रेरणा है।

इस शानदार जीत के बाद क्षेत्र के लोगों और लखनऊ स्थित उपद्धऋ परिवारों में जश्न और गर्व का माहौल है। स्थानीय खेल प्रेमियों ने बच्चों के इस जज्बे की जमकर सराहना की है।

लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बना जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत लखनऊ ने नगरपालिका ठोस कचरे के 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य हासिल कर लिया है

नव स्थापित शिवारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन है

लखनऊ में घर-घर कचरा संग्रहण की दक्षता बढ़कर 96.53 प्रतिशत हो गई है और स्रोत पर ही कचरे को अलग करने का स्तर 70 प्रतिशत से अधिक है

(जीएनएस)।

शिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के शुभारंभ के साथ लखनऊ ने शहरी स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत नगरपालिका ठोस कचरे के 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण को प्राप्त किया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लगभग 40 लाख निवासियों और 7.5 लाख प्रतिष्ठानों के साथ तेजी से विकसित हो रहा एक शहरी केंद्र है। इस तीव्र विकास के कारण अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता में जटिल चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान, संसाधन पुनर्प्राप्ति और सतत शहरी विकास पर केंद्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है, जिससे शहर में जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता दोनों में सुधार हो रहा है।

लखनऊ ने अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति अपने वैज्ञानिक और टिकाऊ दृष्टिकोण के अनुरूप, शिवारी संयंत्र में अपनी तीसरी ताजे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जिसने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल किया है और आधिकारिक तौर पर 'शून्य ताजे अपशिष्ट डंप' शहर का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

नवस्थापित संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। लखनऊ नगर-निगम अब दो मौजूदा संयंत्रों के साथ प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2,100 मीट्रिक टन से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने में सक्षम है। इससे खुले में कचरा फेंकने की आवश्यकता समाप्त हो गई है और यह टिकाऊ शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

शहर में प्रतिदिन लगभग 2,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है। इसके प्रबंधन के लिए लखनऊ नगर निगम और भूमि ग्रीन एनर्जी ने 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले तीन कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए हैं। कचरे को जैविक (55 प्रतिशत) और अजैविक (45 प्रतिशत) भागों में अलग किया जाता है।

प्रयागराज मे माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य स्वामी

(जीएनएस)।

प्रयागराज

#अविमुक्तेश्वरानंद का एक कड़ा और विवादित बयान सामने आया है। यह बयान उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिया है और इसके शब्द उनके अपने हैं।

#बयान का तथ्यात्मक विवरण

शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि वह मंदिर तोड़ने वाला व्यक्ति है। उन्होंने दावा किया कि काशी की गलियों में वे करीब 40 दिन तक मंदिरों को बचाने के लिए निकले, लेकिन इस दौरान कभी 100 से अधिक हिंदू उनके साथ नहीं आए।

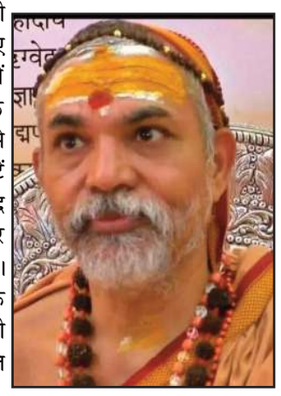

#उन्होंने ज्ञानवापी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि रात में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बुलडोजर से ज्ञानवापी की तीन ईंटें गिर गईं, जिसके बाद करीब 10 हजार मुसलमान इकट्ठा हो गए। इस पर उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने धर्म की रक्षा के लिए संगठित होकर निकलते हैं।

#इसी क्रम में उन्होंने हिंदू समाज को लेकर यह टिप्पणी की कि गौहत्या जैसे मुद्दों पर हिंदू सड़कों पर नहीं उतरते और इसे उन्होंने कायरता बताया।

#तथ्य यह है कि यह बयान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा सार्वजनिक मंच से दिया गया है और वीडियो व बयानों के रूप में मौजूद है। यह एक राय आधारित वक्तव्य है, न कि किसी सरकारी रिपोर्ट या न्यायिक निष्कर्ष का हिस्सा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रशासन या किसी आधिकारिक संस्था की ओर से इस बयान पर फिलहाल कोई पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

#ज्ञानवापी से जुड़ी घटनाओं पर भी आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रशासनिक तथ्य अलग संदर्भ में मौजूद हैं, जिनकी यहां पुष्टि नहीं की गई है।

#यह बयान धार्मिक और सामाजिक तुलना करता है, जो संवेदनशील है। खबर के स्तर पर इतना ही सत्य है कि बयान दिया गया है। इसके दावे और निष्कर्ष अभी प्रमाणित नहीं हैं।

स्थानीय भाषा में बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 8 राज्यों के 8 ग्राम-पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में स्थानीय भाषा में बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया

ग्रामीण समुदायों के साथ स्थानीय भाषा में संवाद जन भागीदारी एवं समुदाय-नेतृत्व वाले जल प्रबंधन को मजबूत करता है

'सुजल ग्राम संवाद' ग्रामीणों को स्थानीय भाषाओं में सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करने का मंच प्रदान करता है, अन्य ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के बीच सहभागितापूर्ण शिक्षण को सक्षम बनाता है

(जीएनएस)।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय ने आज 'सुजल ग्राम संवाद' के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो भारत सरकार की जल प्रबंधन एवं जल जीवन मिशन (जेजेएम) के समुदाय-नेतृत्व वाले कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

इस वर्चुअल संवाद में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य, सामुदायिक प्रतिभागी, महिला स्वयं सहायता समूह, छात्र एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, साथ ही जेजेएम के राज्य मिशन निदेशक, जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, डीडब्ल्यूएसएम अधिकारी और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सुजल ग्राम संवाद के तीसरे संस्करण में आठ ग्राम-पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में ग्राम स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। इस पहल में 3,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो समुदायों एवं अधिकारियों दोनों की मजबूत भागीदारी दर्शाता है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग लोग शामिल थे जिसके कारण सामूहिक भागीदारी पंजीकृत संख्या से कहीं ज्यादा देखी गई।

श्री अशोक के.के. मीना, सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने अपने संदेश में ग्रामीण स्तर पर पेयजल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण तीन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है और इस बात पर बल दिया गया है कि पंचायतों को निरंतर सामुदायिक सहभागिता एवं सहभागितापूर्ण योजना के माध्यम से इस भूमिका को पूरी तरह से निभाना चाहिए ताकि सभी घरों में नियमित एवं विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जल अर्पण एवं लोक जल उत्सव - उन्होंने कहा कि जल अर्पण के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति योजनाओं का औपचारिक मूल्यांकन, प्रवर्तन एवं हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाता है, साथ ही आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। उन्होंने पंचायतों से लोक जल उत्सव आयोजित करने का आग्रह किया ताकि योजनाओं की व्यापक समीक्षा की जा सके और उनका समय पर संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

जल सेवा आकलन - यह एक क्रांतिकारी पहल है जिसमें ग्राम पंचायतों के साथ-साथ ग्रामीण सभाओं के माध्यम से जल की मात्रा, गुणवत्ता एवं सेवा स्तर का आकलन किया जाता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सेवा वितरण में निरंतर सुधार के लिए निष्कर्षों को ग्राम सभा के समक्ष रखना चाहिए और पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।

अपने उद्घाटन भाषण में, श्री कमल किशोर सोन एनजेजेएम के अवर सचिव एवं मिशन निदेशक, ने कहा कि सुजल ग्राम संवाद को एक ऐसा मंच बनाया गया है जहां ग्रामीणों की बात उनकी भाषाओं में सीधे सुनी जाती है जिससे यह पता चल सके कि समुदाय पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव कैसे कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, जिला कलेक्टरों और मिशन निदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि कई पंचायतों ने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है लेकिन मौजूदा चुनौतियों का समाधान ग्राम, जिला, राज्य और केंद्र सरकारों के समन्वित प्रयासों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों एवं मंत्रालय के बीच सीधे संवाद ने जमीनी स्तर के अनुभवों से सीख लेकर मिशन को मजबूत करने में मदद की है।

उन्होंने प्रकाश डाला कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर आमंत्रित किया जाता है ताकि वे दूसरों को प्रेरित कर सकें और उन्होंने व्यापक प्रसार के लिए अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पेयजल आपूर्ति 30 वर्षों तक निरंतर बनी रहनी चाहिए और दोहराया कि स्रोत की स्थिरता, प्रणाली के रखरखाव एवं सेवा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने अपना संबोधन समाप्त कहते हुए कहा कि जल जीवन मिशन केवल एक योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, जिसमें सुजल ग्राम संवाद सतत एवं समावेशी पेयजल सेवा वितरण को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है।

जमीनी स्तर की बातें

1.सिप्पीघाट, दक्षिण अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

श्री समीर कुमार, आर्थिक सलाहकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान जिले के सिप्पीघाट में हिंदी भाषा में समुदाय के साथ बातचीत कर ग्रामीण स्तर पर संवाद की शुरूआत की।

ग्रामीणों ने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसके कारण चिकित्सा खर्चों में बचत हुई है और महिलाओं एवं लड़कियों के लिए कठिन जीवन सुगम हुआ है। सातवीं कक्षा की एक छात्रा ने कहा कि घर और विद्यालय दोनों जगह नल जल की उपलब्धता से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बीमारियों के मामलों में कमी आई हैं और विद्यालयों में प्रतिदिन निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। उसने यह भी कहा कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था है और हाथ धोने की सुविधाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं, जिससे स्वच्छता बेहतर हुई है और विद्यालय का वातावरण स्वस्थ बना है।

2. साल्हेभाट, रायपुर, छत्तीसगढ़

साल्हेभाट के समुदाय ने छत्तीसगढ़ी भाषा में जल संसाधन विभाग के अधिकारी से कहा कि पहले पीने का पानी नदियों एवं नालों से एकत्रित किया जाता था लेकिन अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी घरों में नल के माध्यम से उपलब्ध है, जिनकी गांव के जल टैंक से नियमित एवं समय पर आपूर्ति होती है।

नोडल अधिकारी और प्रधान की अनुपस्थिति में कोटा बैठक स्थित

(जीएनएस)।

फतेहपुर। ऐरायां विकास खंड के मोहम्मदपुर गौंती ग्रामसभा स्थित जनता इंटर कॉलेज में बुधवार को कोटा चयन बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में कार्यवाहक एडीओ पंचायत अर्पण अग्रवाल, एडीओसी राजबली, एडीओ आईएसबी उदयभान सिंह और सचिव बिजेंद्र कुमार गांव पंहुचे। लेकिन बैठक में नोडल अधिकारी के रूप में सीडीपीओ आशीष कुमार पांडेय और ग्राम प्रधान कफील सिद्दीकी के बैठक में न पहुंचने के कारण कोटा बैठक स्थगित करना पड़ा। इसके पहले भी 18.11.24 को कोरम पूर्ण न होने के कारण पहली बैठक स्थगित हुई थी। दूसरी बार बैठक निरस्त होने के कारण ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। करीब एक साल पहले नयापुरवा गांव निवासी कोटेदार रामप्रताप पाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से कोटा रिक्त चल रहा था। प्रत्याशी रामनरेश नामदेव और पप्पू पटेल सहित ग्रामीणों ने बैठक निरस्त की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। कार्यवाहक एडीओ पंचायत अर्पण अग्रवाल ने बताया कि नोडल अधिकारी की एसआईआर में ड्यूटी लगी होने कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, अगली तिथि एसडीएम की तरफ से निर्धारित की जाएगी। इस मौके दिलशाद बाबू, विक्रम सिंह, नियाज अहमद, नसीम उल्ला, सूर्यभान सिंह, शिव सिंह, जीशान अहमद, सहित गांव के लोग बैठक में उपस्थित रहे।

विद्युत मंत्री ने एडिकॉन 2026 का उद्घाटन किया, आर्थिक रूप से मजबूत विद्युत वितरण कंपनियों और बेहतर सेवाओं का आह्वान किया

विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि आने वाले समय में विद्युत क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार होने वाला है। तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था को आज की परिकल्पना से कहीं अधिक एक समृद्ध विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है। ऐसे में, हमारे वितरण और आपूर्ति कंपनियों (डीएससीओ) का मजबूत, समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मजबूत डीएससीओ का अर्थ बेहतर सेवाएं और उपभोक्ताओं की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता है।

आज यहां 'विद्युत वितरण उद्योग सम्मेलन 'एडिकॉनः 2026' के उद्घाटन भाषण के दौरान श्री मनोहर लाल ने कहा कि 21-22 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाला एडिकॉन विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में अखिल भारतीय वितरण संघ (एआईडीए) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

विद्युत मंत्री ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों से लागत के अनुरूप टैरिफ की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया, साथ ही विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जरूरतमंद उपभोक्ताओं के लिए लक्षित सब्सिडी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।

श्री मनोहर लाल ने एआईएसए की वार्षिक रिपोर्ट 'इंडिया डिस्कॉम्सः 2025' के प्रथम प्रकाशन का विमोचन किया, जिसमें वितरण क्षेत्र का विस्तृत विवरण दिया गया है।

संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटे-बहू ने मां-बाप को पीटा, पिता गंभीर रूप से घायल

(जीएनएस)।

खखरेरू / फतेहपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में संपत्ति के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद इस कदर बढ़ गया कि बेटे और बहू ने अपने ही मां-बाप के साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना में वृद्ध पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

गांव निवासी ज्ञानमती देवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके तीन पुत्र हैं। संपत्ति के बंटवारे में बड़े बेटे सुभाष को एक-तिहाई हिस्सा दिया गया था, लेकिन वह पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा करना चाहता था।

इसी बात को लेकर 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे सुभाष और उसके भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

ज्ञानमती देवी द्वारा विवाद शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोप है कि सुभाष और उसकी पत्नी फूलमती देवी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव के लिए पहुंचे ज्ञानमती देवी के पति संतोष कुमार पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट के दौरान ज्ञानमती देवी के कान में तथा संतोष कुमार के नाक में गंभीर चोटें आईं।

घटना की सूचना पर पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा।

थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी सुभाष और उसकी पत्नी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने पुणे में पश्चिमी क्षेत्र के राज्य जल सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता की

जल क्षेत्र में केंद्र-राज्य के बीच साझेदारी को मजबूती

(जीएनएस)।

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी.एल. कांता राव ने जल क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के लिए पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय राज्य जल सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता की।

इस सम्मेलन में समहाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गोवा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के अधिकारियों के अलावा विभाग के प्रमुख संगठनों के प्रमुख भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसमें भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास एवं

कृषि विभाग के विभिन्न संगठनों की सेवाओं/कार्यों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श हेतु ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलनों के आयोजन की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सम्मेलन के मुख्य कार्यसूची में शामिल थे-

विभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनों द्वारा सहभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए कार्यों की समीक्षा।

भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुतियां।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रस्तुतियों पर चर्चा और उनकी समस्याओं/चिंताओं का समाधान।

भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग की सलाह पर अमल की समीक्षा।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल संसाधन क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर प्रस्तुतियां दीं। सचिव ने राज्यों की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और प्राथमिकता वाले कार्यों की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों केक बीच तालमेल में कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अपने समापन भाषण में सचिव ने क्षेत्र में जल संसाधनों के सतत और प्रभावी विकास के लिए एकीकृत रणनीतियों को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में बैठक के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जल संसाधन परियोजनाओं के समग्र विकास और प्रबंधन के लिए पूरी सहायता प्रदान करने की विभाग की प्रतिबद्धता को दोहराया।

शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का भव्य आयोजन

जश्न ए आजादी ने कैंडल जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

लखनऊ।जश्न-ए-आजादी एवं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज 21 जनवरी को सायं 5 बजे ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों की स्मृति में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर दोनों संगठनों के सदस्यों ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का उद्देश्य गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के महत्व को जन-जन तक पहुँचाना तथा राष्ट्र के प्रति नागरिकों में देशभक्ति, जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करना रहा।

सभा में अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा, संरक्षक रज़िया नवाज, रोहित अग्रवाल, मोहम्मद जुबैर, अभय सिंह, अब्दुल वहीद, मुर्तजा अली, वामिक खान, कुदरत उल्ला खान , हलीमा, कैफ, डॉ अंजुम, निहिल श्रीवास्तव, फहद, अमरजीत कुरील, अवधेश सोनकर, एडविन मौसी, जशवीर गांधी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आजादी और संविधान की रक्षा के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।